खबर संक्षेप

एक वर्ष में मालवा-निमाड़ के बिजली उपभोक्ताओं को 9161 करोड़ की सब्सिडी

भोपाल। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राज्य शासन की जनहितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर औसत 46.72 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिमाह लाभान्वित कर रही है। इसी बारह माह के दौरान कुल 9161 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि शासन का उद्देश्य बिलों में राहत प्रदान करना और प्रदेश के विकास में निर्बाध बिजली के माध्यम से भूमिका निभाना है। विद्युत वितरण कंपनी इसी दिशा में कार्य कर राहत पहुंचा रही हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि औसतन प्रतिमाह अटल गृह ज्योति योजना में 31.82 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर वर्ष में 1748.73 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह अजा और अजजा के पात्र 4.80 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी गई , इसके लिए 2493.66 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी गई है। अटल कृषि ज्योति योजना में 9.94 लाख किसानों को 4607.55 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। प्रबंध निदेशक सिंह ने बताया कि कृषि में 10 एचपी से ज्यादा शक्ति के पंप वाले करीब दस हजार किसानों को 141.39 करोड़ की और उच्चदाब कनेक्शन से संबंधित किसानों को 143.90 करोड़ की सब्सिडी दी गई हैं।

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 106 छात्रावास में 8,850 सीटें

भोपाल। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये विभिन्न नगरों में पोस्ट-मैट्रिक के छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 106 छात्रावास हैं और इनमें 8 हजार 850 सीट उपलब्ध हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण संचालनालय द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 50 सीटर कन्या छात्रावास की संख्या 51 है। इनमें 2550 छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 100 सीटर कन्या छासावास की संख्या 2 है इनमें 200 छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 500 सीटर कन्या छात्रावास की संख्या भी 2 है, जिनमें एक हजार छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के 100 सीटर बालक छात्रावास की संख्या 51 है, जिनमें 5100 छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक के कन्या एवं बालक छात्रावासों में निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

आजीविका मिशन से मिली अभिलाषा पटेल को आत्मनिर्भरता की उड़ान

भोपाल। छतरपुर जिले के लवकुशनगर विकासखंड के ग्राम अमहापुरवा की श्रीमती अभिलाषा पटेल ने मध्यप्रदेश आजीविका मिशन और अटइयाबाबा स्व-सहायता समूह के सहयोग से आर्थिक तंगी को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। पहले पारंपरिक कृषि पर निर्भर अभिलाषा और उनके पति अखलेश को कम आय से परिवार चलाना मुश्किल था। लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के संकल्प को साकार करते हुए ÷लखपति दीदी÷ बना दिया। अगस्त 2017 में अभिलाषा अटइयाबाबा स्व-सहायता समूह की सदस्य बनीं। समूह से 12,000 रुपये का ऋण लेकर उन्होंने किराना दुकान शुरू की। वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ और काम या व्यवसाय भी करना चाहती थीं।गांव में आयोजित समारोह में टेंट की कमी को अवसर मानकर उन्होंने पति के साथ टेंट हाउस खोलने का फैसला लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 18 करोड़ से निर्मित सर्वसुविधायुक्त स्नेहधाम का किया लोकार्पण

बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और सुरक्षा हमारी संस्कृति का हिस्सा: मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में स्नेहधाम भवन के लोकार्पण अवसर पर कहा कि यह प्रकल्प केवल सामाजिक सुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षित आवास सुविधा भी सुनिश्चित करता है। यह अपने आप में एक बड़ा और संवेदनशील कदम है, जो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और सुरक्षा हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंदौर में 18 करोड़ रुपये की लागत से स्नेह धाम भवन इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। प्रदेश में अपने तरह की इस पहली अभिनव पहल का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। स्नेहधाम भवन में बुजुर्गों के लिए भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन, स्वाध्याय, ध्यान और परामर्श जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यहां बुजुर्गों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकार्पण अवसर पर इंदौर को 565 करोड़ रुपये से अधिक के लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर लगभग 90 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण

किया और 476 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, मनोज पटेल तथा गोलू शुक्ला, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और संभागायुक्त दीपक सिंह भी विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय के साथ सामाजिक ढांचा बदला है कई बुजुर्ग दंपत्ति आज अकेले हैं, किसी के बच्चे विदेश में हैं तो कोई नौकरी के कारण दूर शहरों में रहते हैं ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, आत्मसम्मानजनक और सुसज्जित आवास की आवश्यकता को स्नेहधाम जैसी पहलें पूरा करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं, बल्कि सामाजिक नवाचारों और जनकल्याण की दिशा में भी लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा।

सर्व सुविधायुक्त स्नेह धाम- प्रदेश में अपने तरह की पहली अभिनव पहल

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक अभिनव पहल की है। योजना क्रमांक 134 के अंतर्गत लगभग 20 हजार वर्गफीट के भूखंड पर स्नेहधाम सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यह भवन प्रदेश में अपने तरह का पहला है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ सर्व सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की गई है। इस 6 मंजिला भवन में कुल 32 फ्लैट बनाए गए हैं। जिसमें 2 BHK के 22 फ्लैट तथा 1 BHK के 10 फ्लैट शामिल हैं। लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भवन में वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल सभी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। परिसर में 24×7 सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और डीजी सेट से बैकअप की भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो लिफ्ट भी रहेगी। प्रत्येक फ्लेट में 24×7 पानी, बिजली, गीजर, स्टडी टेबल, सोफा, टी.वी., फ्रिज, माइक्रोवेव, आदि सुविधाएँ हैं। कॉल करने पर चाय, नाश्ता, भोजन की रूम सर्विस भी रहेगी। साथ ही प्रथम तल पर मॉड्यूलर किचन, स्टाफ, डाइनिंग हॉल आदि हैं। प्रातः चाय से लेकर रात्रि भोजन तक की सभी व्यवस्थाएँ की गई है। भोजन का मीनू भी सर्वसम्मति से तय होगा। परिसर में वॉक करने के साथ-साथ इनडोर गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, कैरम, चैस आदि की सुविधा उपलब्ध है। योग, प्राणायाम हेतु भी पृथक से प्रशिक्षक रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से नियमित चेकअप के लिए नर्सिंग स्टाफ 24×7 रहेगा। विस्तृत जांच व उपचार हेतु निकटतम अस्पताल से अनुबंध किया गया है ताकि तत्काल उपचार प्राप्त हो सके। संपूर्ण परिसर में 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह भवन वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर आवास सुविधा प्रदान करने के साथ सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा जहाँ वे अपने जैसे ही नागरिकों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का श्रीमती मनीषा भटनागर ने माना आभार

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इजरायल-ईरान युद्ध के चलते कतर से वापसी के लिये रह गई उज्जैन निवासी श्रीमती मनीषा भटनागर की सकुशल स्वदेश वापसी के बाद उनसे वीडियो कॉल पर चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार बहन-बेटियों को हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। श्रीमती भटनागर ने उज्जैन वापसी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। उन्होंने कहा कि कतर से भारत लौटने में प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग मिला। संकट के क्षणों में पूर्ण विश्वास था कि देश और प्रदेश की सरकार हमारी चिंता कर रही है और हम निश्चित ही सुरक्षित स्वदेश लौटेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती भटनागर से एयरलाइंस में उनके कामकाज की जानकारी भी ली। उल्लेखनीय है कि श्रीमती भटनागर कतर एयरवेज में सीनियर केबिन क्रू हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनकी सकुशल वापसी के लिए केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से सहयोग के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हुए श्रीमती भटनागर की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक

नर्मदा घाटी परियोजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदा नदी राज्य की जीवनदायिनी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित गतिविधियों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे और ऊर्जा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है जिसके चलते प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत निर्मित सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। जल उद्वहन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने से बिजली पर होने वाले व्यय में कमी लाई जा सकेगी। किसानों को भी सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। मां नर्मदा के जल का प्रदेश हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री मनीष रस्तोगी सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में शहीद ईलाप सिंह माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला हरदा, सेंधवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, निवाली उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, धार उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, मॉ रेवा उद्वहन सिंचाई

परियोजना जिला देवास की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डोबी सिंचाई परियोजना, भीकनगांव बिंजलवाडा माईक्रो सिंचाई परियोजना, आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना, खालवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला खण्डवा की समयवृद्धि प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोरंड गंजाल बांध एवं दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के निर्माण में आईएसपी जलाशय और अपर नर्मदा परियोजना के कमाण्ड में निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में विजयराघवगढ़ उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, गुनौर माईक्रो सिंचाई परियोजना, झिरन्या एक्सटेंशन (विस्तार) माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव चरगंवा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना, खेड़ी बुजुर्ग उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला धार की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में नर्मदा नदी के धार्मिक एवं सामाजिक और पर्यटन महत्व के स्थलों पर घाट निर्माण के संबंध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसाबंदियों का संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों जैसा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं बरसी पर कहा है कि गणतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने आपातकाल के संघर्ष में कुर्बानी दी है। इसी का प्रतिफल है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत में संघ परिवार ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे मार्गदर्शक श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा श्रद्धेय मोरारजी देसाई सहित विपक्ष के सभी नेताओं ने एक स्वर में आपातकाल का विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यह स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। इसीलिए सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम मिला है।

गुना में दुर्घटना स्थल पहुंचे प्रभारी मंत्री राजपूत

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता, घटना की जांच के आदेश

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र के गांव धरनावदा में घटित दुर्घटना के बाद जिले के प्रभारी एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंगलवार रात में ही गुना पहुंचें। उन्होंने बुधवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटना स्थल का दौरा किया। राजपूत ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढाढस बंधाया। मंत्री राजपूत ने बताया कि घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की और मुख्यमंत्री जी को घटना के संबंध में अवगत करवाया गया। घटना बहुत ही दुखद है। राज्य सरकार दु:ख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दिए गए है ताकि घटना के सही कारणों का पता चल सके।

सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कराएँ जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी: मंत्री तोमर

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

बरसात के दौरान जिन-जिन स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन रही है, यदि उन स्थानों पर पक्के नाले नहीं बनाए जा सकते तो अस्थाई नाली-नाले बनाकर जल निकासी कराएं। साथ ही जरूरत के मुताबिक पंप लगाकर भी पानी के निकास की व्यवस्था कराई जाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश बुधवार को उप नगर ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी कराने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से कराएं। तोमर ने खुले चैंबरों में ढक्कन लगवाने और सीवर लाइनों की सफाई कराने पर भी विशेष जोर दिया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने उप नगर ग्वालियर की विभिन्न बसाहटों में जहाँ-जहाँ वर्षा जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, उन स्थानों की जानकारी दी। उन्होंने नगर निगम द्वारा उन क्षेत्रों में जल निकासी के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनती है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की विशेष व्यवस्था की जाए, जिससे रात्रि के समय दुर्घटना की स्थिति न बने। मंत्री तोमर ने बैठक में कहा कि एलीवेटेड रोड के प्रथम चरण का शेष काम तेजी से पूर्ण कराएं।

निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी

9 हजार से अधिक बच्चों को मिला मनचाहे विद्यालयों में प्रवेश

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की गई द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 9 हजार 190 बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हुआ है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने बुधवार को भोपाल में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी का बटन क्लिक किया। इस लॉटरी प्रक्रिया में उन बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्हें प्रथम चरण की लॉटरी में उनकी पंसद के स्कूल आवंटित नही हो सके थे। ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों की रिक्त सीटों अनुसार द्वितीय चरण की लॉटरी के लिये अपनी वरीयता अंकित करते हुए आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया गया था। द्वितीय चरण की लॉटरी में बच्चों को उनकी चुनी गई वरीयता के आधार पर निजी विद्यालयों में सीट का आवंटन 25 जून को ऑनलाइन लॉटरी की स्वचालित कंप्यूटर प्रक्रिया द्वारा किया गया। इनमें से 5 हजार 128 बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें उनके द्वारा चयनित प्रथम वरीयता वाले स्कूलों में प्रवेश मिला है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने लॉटरी में चयनित बच्चों को उनकी पसंद का स्कूल आवंटित होने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था निर्मित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टीम की प्रशंसा भी की। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष आरटीई के तहत लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत एक लाख 66 हज़ार 751 बच्चे पात्र हुए थे, जिनमें से 83 हजार 483 बच्चों को प्रथम चरण की ऑनलाइन लॉटरी में उनके द्वारा चयनित स्कूलों का आवंटन किया जा चुका है। बुधवार को आयोजित हुई द्वितीय चरण की लॉटरी में 9 हजार 190 और बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में प्रवेश आवंटन प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आवंटन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 92 हजार 673 हो गई है। जिन बच्चों को आज इस ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल का आवंटन हो रहा है, उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। बच्चे उनके आवंटित स्कूलों में 30 जून तक जाकर प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सीधे स्कूल के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री निवास भोपाल में 26 जून को होगा लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किदेश में लोकतंत्र की रक्षा में अनेक सेनानियों ने योगदान दिया है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रभक्त कारावास गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में गुरुवार 26 जून को लोकतंत्र सेनानियों के स्वागत का सौभाग्य मिल रहा है। प्रदेश में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपालन में बुधवार 25 जून से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, जो 25 जून 2026 तक चलेंगे। प्रदेश में 25 जून को इंदौर में विशेष कार्यक्रम के बाद भोपाल में 26 जून को प्रादेशिक लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को लोकतांत्रिक इतिहास का काला दौर मानते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है।

प्रदेश में जनभागीदारी से होंगी वर्ष भरविविध गतिविधियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में 25 जून 2025 से 25 जून 2026 तक संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में विभिन्न विभाग कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आपातकाल की अवधि में नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक निलंबन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों के क्षरणऔर व्यापक उत्पीड़न के दौर को लोकतंत्र पर धब्बा माना गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनभागीदारी के साथ कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी संभागायुक्त और कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में मशाल यात्राओं के आगमन पर प्रदर्शनी और फिल्म प्रदर्शन के कार्यक्रम करवाएंगे। नई दिल्ली से प्रारंभ हो रही छह मशाल यात्राएं देश के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेंगी। निर्धारित कार्यक्रमों में भारत की लोकतांत्रिक परम्परा और इसके आयामों पर निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और संगोष्ठियों का आयोजन भी शामिल है।